



# सम्पादकीय....

# गहरी राजनीति चाल

केंद्र की राजग सरकार ने एक महत्वपूर्ण एवं साहसिक आदेश के जरिये सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगी रोक को हटा कर लोकतांत्रिक एवं सर्वैधानिक भावना एवं मूल्यों का जीवंत किया है। भले ही इस आदेश को लेकर विपक्षी राजनीतिक दलों की तल्ख प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं संघ ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि तत्कालीन सरकार ने निराधार ही शासकीय कर्मियों के संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर रोक लगायी थी। निश्चित ही वर्तमान सरकार का यह निर्णय लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक गैर-राजनीतिक संगठन है, गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण एवं समाज की सेवा में संलग्न संघ एक रचनात्मक, सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक संगठन है। राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता-अखंडता एवं प्राकृतिक आपदा के समय में संघ के योगदान की विभिन्न राजनीतिक विचारधारा के नेताओं एवं दलों ने प्रशंसा भी की है। इस नये आदेश को लेकर इंडी गठबंधन के दलों में खलबली एवं बौखलाहट का सामने आना स्वाभाविक है, क्योंकि इस आदेश से संघ की ताकत बढ़ेगी, जो इन विपक्षी दलों की चिन्ता का बड़ा कारण है।

दरअसल, आरोप है कि पूर्व की काग्रेस सरकारों ने समय-समय पर सरकारी कर्मचारियों की संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर कर्मचारियों को कड़ी सजा देने तक का प्रावधान लागू किया गया था। सेवानिवृत होने के बाद पेशन लाभ इत्यादि को ध्यान में रखते हुए भी अनेक सरकारी कर्मचारी चाहते हुए भी संघ की गतिविधियों में शामिल होने से बचते थे। हालांकि, इस बीच मध्यप्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने इस आदेश को निरस्त कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार के स्तर पर यह वैध बना हुआ था। इस मामले में एक बाद इंदौर की अदालत में चल रहा था, जिस पर अदालत ने केंद्र सरकार से सफाई मांगी थी। इसी पर कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने नौ जुलाई को एक ऑर्डर जारी करते हुए उक्त प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा कर दी। निश्चित ही यह आदेश संघ से जुड़े एवं राष्ट्रीय विचारधारा वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये एक नयी किरण है। आपातकाल में इंदिरा गांधी सरकार की तानाशाही खुलकर सामने दिखी थी, लेकिन उससे पहले भी तानाशाही कदम उठाए जाते रहे थे। दरअसल, 7 नवंबर 1966 को संसद के सामने गोहत्या के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था। 30 नवंबर 1966 को संघ-जनसंघ के प्रभाव से हिलकर इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों के संघ में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि संघ व जनसंघ के प्रयासों से

आओ मिलकर ले संकल्प,  
करे गाय का संरक्षण



ब्यूरो चीफ हिमांशु सिंह राजपूत/  
नवयुग समाचार दमोह  
हटा/दमोह मध्य प्रदेश

वर्तमान स्थिति के अनुसार गायों की हालत हमारे देश में बहुत बुरी हो चुकी है अगर बात करें गायों की तो जब तक गौमाता दूध देती है तो लोग उसे अपने घर में रखते हैं दूध न देने पर गौमाता को घर से बाहर निकल देते हैं। अगर पशुधन की गड़ना के आंकड़ों के अनुसार भारत में 47% गौमाता आवारा गयों की तरह सड़क

है आखिर में देखा जाये तो हमने ही इन बेजुबान जीवों को आवारा बनाया है हम बिना सोचे समझे उन्हें युही छोड़ देते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ गायों को पवित्र और पूजनीय माना जाता है, वहीं भारत में सबसे अधिक प्रताड़ित जीवों को ही किया जाता है। डेयरी के लिए मानवीय मांग को पूरा

करने के लिए गायों के ऊपर बहुत अत्याचार किया जाता है। भारत में गाय का विशेष कोई कानून भी नहीं है। हम चाहते हैं कि गाय को माता का दर्जा दिया जाये और गाय को पूज्य माना जाये। सभी गाय कि सेवा करें और रक्षा करें। दिनांक 24/07/2024 शाम को उपकाशी नगरी हटा के अधियारा बंगीचा में गौ माता के पैर में घाव होने जानकारी मिलते ही सुरभी गौ ने वा समिति के संचालक श्री अंशु तिवारी जी एवं उनकी टीम 3 हृषभवती मानव कल्याण संगठन शाखा हटाह उपाध्यक्ष सुर्न रैकवार (सागर भैया) एवं गुरु तेकाम ने गौ माता के पैर में दबाए एवं मलहम पट्टी की

उन्नाव जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष अरुण सिंह एवम सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजय पाण्डेय को किया गया सम्मानित

ਮोहम्मद इरफान ख

लखनऊ लखनऊ के चौधरी चरण सिंह सहकारिता भवन स्थित सभागार में आयोजित एक दिवसीय सहकारिता कॉन्फ्रेंस में उन्नाव जनपद को दो पुरस्कार प्राप्त हुए सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)



एवम निबंधक अनिल कुमार की उपस्थिति में उन्नाव जिला सहकारी बैंक को निष्क्रेप, ऋण वितरण, एवं वसूली, ओवरऑल परफॉर्मेंस में प्रथम पुरस्कार के साथ एवम सदस्यता अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु अरुण सिंह अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक उन्नाव एवम सचिव मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजय पांडे को सम्मानित किया गया ...  
जनपद का सहकारिता परिवार बैंक को मिली इस उपलब्धि से अपने

आप को गौरावित महसूस कर रहा है उल्लेखनीय है प्रदेश में सदस्यता महा अभियान में चतुर्थ स्थान प्राप्त करना एवं कार्य कुशलता व परफॉर्मेंस में पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर जनपद की सभी शाखाएं लाभ पर एवम प्रगति की ओर अग्रसर है

विपक्ष की मुस्लिमों के प्रति अंधश्रद्धा से भाजपा बनी मजबूत

मुस्लिमों का हितेषी बनने का नया मामला बांग्लादेश का है। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हिंसा प्रभावित बांग्लादेश के संकटग्रस्त लोगों के लिए पश्चिम बंगाल के दरवाजे खुले रखेंगी और उन्हें आश्रय देंगी। मुस्लिम वोटों के लिए विपक्षी नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं। विपक्षी दलों को लगना चाहिए कि हितेषी बनने का दिखावा करने मात्र से मुस्लिम वोटों को बटोरा जा सकता है।

मे आपस में ही सच्चा हितेषी  
साबित करने की प्रतिष्पर्धा  
हो जाती है। वोटों की खातिर  
मुस्लिमों के प्रति इस अंधश्रद्धा  
का ही परिणाम है कि इसके  
प्रतिक्रियास्वरूप भाजपा ने न  
सिर्फ राष्ट्रीय पर संगठन की  
मजबूत पकड़ बना ली,  
बल्कि लगातार तीसरी बार  
केंद्र में सत्ता में भी आ गई।  
हालांकि इसमें काफी हद तक  
केंद्र सरकार के विकास कार्य  
भी शामिल हैं।  
मुस्लिमों का हितेषी बनने का

पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हिंसा प्रभावित बांग्लादेश के संकटग्रस्त लोगों के लिए पश्चिम बंगाल के दरवाजे खुले रखेंगी और उन्हें आश्रय देंगी। आश्र्य की बात यह है कि यह मुद्दा मुख्यमंत्री ममता के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। यह विदेश मंत्रालय के अधीन आता है। विदेश मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन काम करता है। यह जानते हुए भी ममता ने मुस्लिम वोट बैंक पर विश्वास दिया है कि ऐसा बयान दिया। इससे पहली ममता बनर्जी सरेंडर मुस्लिमों का पक्ष लेती रहती हैं। इसके लिए बेशक कानून की मंजूरी हो या नहीं। बर्मा रोहिंग्या शरणार्थियों का मस्तक भी केंद्र सरकार के अधीन था। केंद्र सरकार ही तय करकती है कि भारत में किस शरण देनी और किसे नहीं बांग्लादेश ने विरोध जताया। रोहिंग्या शरणार्थी संकट केंद्र के दृष्टिकोण का विरोध करते हुए ममता ने कहा था कि वहाँ जाने को अनिवार्य है।

नहीं है और उन्होंने समुदाय का समर्थन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। गैरतलब है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा 40,000 रोहिंग्या शरणार्थियों को निर्वासित करने की योजना बनाई थी। ममता बनर्जी की शह पाकर कई मुस्लिम संगठनों से जुड़े हजारों प्रदर्शनकारियों ने कोलकाता में रैली निकाली और प्रधानमंत्री मोदी की निर्वासन योजना का विरोध किया तथा रोहिंग्या रिटोर्नेंटों के लिए भेजे गए अधिकारी ने इसमें दूसरे विपक्षी दल भी कूद गए। मुस्लिमों के मामले में सभी विपक्षी दलों को लगता है कि कहीं दूसरा दल वोट बैंक का ज्यादा हिस्सा नहीं ले जाए, इसी वजह मुद्दा चाहे राज्यों का हो या फिर केंद्र सरकार से जुड़ा हो, बहती गंगा में हाथ धोने से कोई पीछे नहीं रहना चाहता। मुस्लिम वोट की खातिर ममता किसी भी हद तक नहीं ले सकती है।

इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत युवाओं को पांच वर्षों के दौरान मिलेगा काम



है। आज पूरे विश्व में केवल भारतीय अर्थव्यवस्था ही एक चमकते सितारे के रूप में दिखाई दे रही है। बजट का गहराई से अध्ययन करने पर ध्यान में आता है कि केंद्र सरकार ने अब भारत में रोजगार के अधिकतम अवसर निर्मित करने की ठान ली है। भारत के युवाओं एवं महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं कौशल विकसित करने की दृष्टि से 2 लाख करोड़ रुपए की 5 योजनाओं के एक पैकेज की घोषणा की है। शिक्षा, रोजगार एवं कौशल विकास के लिए 1.48 लाख

करोड़ रुपए की राशि इस बजट में आवंटित भी कर दी गई है। प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत एढ्रॉफ के प्रथम बार सदस्य बनने पर औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों के एढ्रॉफ खातों में एक माह का वेतन जमाकिया जाएगा। इन कर्मचारियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के अंतर्गत एक माह का वेतन (15000 रुपए की अधिकतम राशि तक) तीन किश्तों में उनके खातों में जमाकिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत एक माह में एक लाख रुपए तक का वेतन पाने वाली कर्मचारी ही पात्र होंगे। इससे

2.1 करोड़ युवाओं को लाभ होने की सम्भावना बजट में व्यक्त की गई है। ऐसे भी कई निर्णय लिए जा रहे हैं जिनसे आने वाले समय में धरातल पर युवाओं को लाभ होता दिखाई देगा। एक करोड़ युवाओं को आगामी 5 वर्षों के दौरान इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत काम दिया जाएगा। ताकि ये युवा वर्ग के नागरिक रोजगार प्राप्त करने हेतु सक्षम हो सकें। इन युवाओं को प्रति माह 6,000 रुपए तक का वाजीफा सम्बंधित कम्पनियों द्वारा अदा किया जाएगा। वजीफे की इस राशि को कम्पनियों के लिए लागू निगमित सामाजिक दायित्व योजना के अंतर्गत किया गया खर्च माना जाएगा। भारत की सबसे बड़ी 50 कम्पनियों को इस योजना अंतर्गत युवाओं को इंटर्नशिप की सुविधा देनी होगी। साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा भी 50 युवाओं को प्रतिमाह 500 रुपए अदा किए जाएंगे। ये केंद्र सरकार का एक सूझबूझ भरा निर्णय कहा जा सकता है। साथ ही, विनिर्माण के क्षेत्र रोजगार के नए अवसर निर्माण करने की पहल भी की रही है। नए कर्मचारियों एड्डरूल खाते में जमा होने वाले

राशि को आगामी 4 वर्षों तक केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, इससे कर्मचारी एवं नियोक्ता दोनों को ही लाभ होगा। इस योजना का लाभ 30 लाख युवाओं को होने जा रहा है। एक अन्य योजना के अंतर्गत नियोक्ता को अपने नए कर्मचारियों के एढ़ब्रह्म खातों में जमा की जाने वाली राशि की प्रतिपूर्ति आगामी 2 वर्षों तक केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। इससे रोजगार के 50 लाख नए अवसर निर्मित होने की सम्भावना है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही के समय में भारतीय सनातन संस्कृति के संस्कारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धार्मिक पर्यटन को देश में बढ़ावा दिया जा रहा है। धार्मिक पर्यटन से देश में रोजगार के लाखों अवसर निर्मित हो रहे हैं एवं गरीब वर्ग की आय में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। श्री विष्णुपाद मंदिर कोरिडोर, गया, बिहार एवं श्री महाबोधि मंदिर कोरिडोर बोधगया, बिहार को विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। इसे काशी विश्वनाथ मंदिर कोरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसी प्रकार देश में अन्य मंदिरों को भी विकसित किया जा रहा है ताकि देश में इन मंदिरों में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असविधा नहीं हो तथा भारत को वैश्विक पटल पर एक बहुत बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में दिखाया जा सके।

भारत के ग्रामों में निवास कर रहे नागरिक रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से शहरों की ओर पलायन करते हैं। अतः ग्रामों में ही रोजगार के अधिकतम अवसर निर्मित करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास की मद पर 2.66 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। साथ ही, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली ऋण राशि की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। यह सुविधा तरुण श्रेणी के अंतर्गत प्राप्त ऋण के व्यवसाईयों को प्राप्त होगी एवं जिन्होंने पूर्व में लिए गए 10 लाख रुपए के ऋण की राशि को समय पर अदा कर दिया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए भी ऋण की सीमा को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत एक करोड़ आवासों का निर्माण किया जाएगा। इन एक करोड़ आवासों पर 10 लाख करोड़ रुपए की राशि का निवेश होगा।



